### मेडिकल कॉलेज में आवश्यकतानुसार मैनपॉवर की व्यवस्था के लिए तैयार करें प्रस्ताव

# नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र करें पूर्णः उप मुख्यमंत्री

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर कर्मचारी चयन मण्डल को त्वरित रूप से मांग पत्र प्रेषित किए जाएं। फार्मासिस्ट ग्रेड-2, नेत्र सहायक तथा ओ.टी. टेक्नीशियन के पदों की पूर्ति के लिये भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के भी निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स से नियुक्ति संबंधी वर्तमान व्यवस्था में केवल अकुशल पदों की स्वीकृति है, जबकि विभागीय समिति द्वारा कुशल पदों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस विषय में व्यावहारिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार कर केबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिससे उच्च स्तरीय सेवाओं का विधिवत एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदाय सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में विभागीय योजनाओं, भर्ती प्रक्रिया, अधोसंरचना विकास, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता की वृहद समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ग्वालियर

मेडिकल कॉलेज में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग की स्थापना के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे हृदय रोगों विशेष रूप से बायपास सर्जरी की सुविधा ग्वालियर संभाग में सुलभ हो सके। इसी प्रकार इंदौर मेडिकल कॉलेज में नवजात एवं बाल चिकित्सा (पीडियाट्रिक्स/नियोनेटोलॉजी) विभाग की स्थापना की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पूर्व की निवेश नीति के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिये। बंधपत्रधारी चिकित्सकों की जिला स्तर पर कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को सेवा की महत्ता, दायित्व एवं प्रभावी संचालन के लिए प्रेरित करना और ज़िम्मेदारियों से अवगत होना आवश्यक है जिससे उनकी उपयोगिता को बेहतर बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने एचआरपी (हाई रिस्क प्रेगनेंसी) केंद्रों पर धात्री महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही कक्ष में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिससे उनकी देखभाल सहज, सुरक्षित और समेकित रूप में संभव हो सके।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन एवं नियामक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तन की कार्यवाही की समीक्षा की और शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 600 आयुष मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पतालों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए भी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिससे कानूनी प्रकरणों एवं पोस्टमार्टम संबंधी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

***मेडिकल कॉलेजों में ऑन्को सर्जरी विभाग की स्थापना के निर्देशः***

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आउटसोर्स मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब की स्थापना के लिए दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएम-अभीम) अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग वर्ष 2026 तक पूर्ण रूप से सुनिश्चित किए जाने के लिए समयबद्ध योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में ऑन्को सर्जरी विभाग की स्थापना के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। जिससे प्रदेश के हर क्षेत्र में कैंसर रोगियों को उत्कृष्ट उपचार सुविधा मिल सके। बैठक में प्रमुख सचिव संदीप यादव एवं आयुक्त तरुण राठी उपस्थित रहे।

# अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी हमारा लक्ष्यः मुख्यमंत्री

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश की भागीदारी और उपलब्धियां बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग दे रही है। वर्ष 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक सहित सभी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और बड़ी संख्या में पदक लाएं, इस लक्ष्य के साथ प्रदेश में खेल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश में खेल अधोसंरचना विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्य सहायता व प्रोत्साहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य शासन मध्यप्रदेश ओलंपिक संघ को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश ओलंपिक संघ की जबलपुर में आयोजित वार्षिक बैठक को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअली शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण श्री मनु श्रीवास्तव इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ओलंपिक संघ वर्ष 1952 से अर्थात् 73 साल से खेल के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है। मध्यप्रदेश का 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और प्रदेश ने पहली बार तीसरा स्थान प्राप्त किया। मध्यप्रदेश में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में 22 से ज्यादा हॉकी के एस्ट्रोटर्फ हैं और 15 एथलेटिक ट्रैक हैं, जो कि देश में किसी भी प्रदेश में नहीं है। मध्यप्रदेश में 18 एक्सीलेंस एकेडमी हैं।

## ऊर्जा विभाग में रिक्त पदों के लिये आवेदन आंमत्रित

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) में विभिन्न श्रेणियों के 633 रिक्त पदों पर भर्ती के लिये योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आंमत्रित किये गये हैं। रिक्त पदों में सहायक अभियंता, विधि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, ट्रांसमिशन लाइन परिचारक, उपकेन्द्र परिचारक, सर्वेयर परिचारक के पद शामिल हैं। इन पदों के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 अगस्त 2025 है। रिक्त पदों में द्वितीय श्रेणी के सहायक अभियंता (पारेषण) के 63 पद, विधि अधिकारी के 01, कनिष्ठ अभियंता पारेषण के 247, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 12, ट्रांसमिशन लाइन परिचारक के 67, उपकेन्द्र परिचारक के 229 एवं सर्वेयर परिचारक के 14 पद शामिल हैं।

# फील्ड अधिकारियों को दिन में एक बार हाजिरी लगानी होगी

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों के लिए सैल्फी अटेंडेंस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब फील्ड अधिकारियों जिनमें जे.ई. एवं उससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं, को दो बार उपस्थिति दर्ज करने के स्थान पर दिन में कार्यालयीन समय में एक बार उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कंपनी ने कहा है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बढ़ती चुनौतियों एवं कार्य आवश्यकताओं को देखते हुए यह पाया गया है कि फील्ड अधिकारी अक्सर रखरखाव, विद्युत आपूर्ति और अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए मैदानी भ्रमण पर रहते हैं, जिससे वे उपस्थिति समय-सारणी का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में फील्ड कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और अधिकारियों की मैदानी आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (ओएंडएम), एसटीएम/एसटीसी/, सतर्कता, बीआई सेल तथा सिविल विभागों में फील्ड ड्यूटी पर तैनात कनिष्ठ अभियंता (जेई) एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को 'अटेंडेंस पोर्टल 2.0' पर दो बार सैल्फी उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फील्ड ड्यूटी पर लगे जे.ई. एवं उससे ऊपर के फील्ड अधिकारी किसी भी सुविधाजनक समय पर केवल एक बार उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। हालांकि कॉर्पोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी या फील्ड इकाइयों में केवल कार्यालयीन कार्य कर रहे अधिकारी, पूर्ववत दो बार उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली का पालन पूर्ववतः करते रहेंगे।

# पोषण ट्रेकर ऐप का प्रशिक्षण निचले अमले को अवश्य देंः मंत्री भूरिया

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि प्रदेश में पोषण ट्रेकर एप के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों के शारीरिक माप (ऊंचाई, वजन एवं आयु के अनुपात में पोषण स्थिति) से संबंधित आंकड़ों का सतत विश्लेषण किया जा रहा है। इन आकड़ों के आधार पर राज्य में पोषण स्तर में सुधार के लिए त्वरित एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना बनाई जा रही है।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि पोषण ट्रेकर ऐप न केवल बच्चों के शारीरिक माप बल्कि बच्चों के कुपोषण की स्थिति में बोनापन, कम वजन की पहचान में भी सहायक है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि निचले स्तर के अमले इस ऐप का उपयोग सही तरीके

से कर रहे है अथवा नहीं। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, सुपरवाइजर सभी को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि निरंतर मॉनिटरिंग करने से त्रुटि को पकड़ा जा सकेगा। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि जिस तरह झाबुआ जिले में मोटी आई के कन्सेप्ट से कुपोषण में कमी हुई है। इसी तरह अधिकारियों को नवाचार करना चाहिए। हर बच्चे का रिकार्ड रखें, उनकी निगरानी करें और अधिक कमजोर बच्चों को चिकित्सीय सहयोग उपलब्ध कराएं। अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने कहा कि पोषण ट्रेकर ऐप के आँकड़े और वास्तविक आँकड़ों मे फर्क इसलिए दिखता है क्योंकि हम सही मॉनिटरिंग नहीं कर रहे है। हर स्तर पर डेटा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहॉ बालिकाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू कि गई, महिलाओं को हर महीने लाड़ली बहना के तहत निश्चित राशि अंतरित की जा रही है, पर इस बात की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि महिलाएं इस राशि का उपयोग कर अपने बच्चों के पोषण पर ध्यान रख रही है अथवा नहीं। अपर मुख्य सचिव श्रीमती शमी ने कहा कि यह कार्यशाला डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप एक डेटा-ड्रिवन अप्रोच के द्वारा प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने और उन्हें सुपोषण की ओर ले जाने मे महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी वली ने कहा कि कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके अनेक कारण है। जिस क्षेत्र मे कुपोषण के आँकडे बड़े हुए है, वहां पर संबंधित अधिकारी को हर स्तर पर इसकी जाँच करना होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी को एनआरसी की पूरी जानकारी होना चाहिए कि उसमें कितने बेड खाली है, डॉक्टर्स से निरंतर बात कर ब्रूरू ब्रूरू बच्चों की जानकारी लें। कुपोषण को दूर करने लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आयुक्त श्रीमती वली ने कहा कि पोषण ट्रेकर ऐप में सही उपयोग से कुपोषण की पहचान करना, समय पर हस्तक्षेप करना और कुपोषण को कम करना संभव है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के बीच कनवेंजेन्स सुनिश्चित करके अधिक प्रभावी ढंग से काम किया जा सकता है।

इस अवसर पर संयुक्त संचालक श्रीमती स्वर्णिमा शुक्ला ने पीपीटी के माध्यम से पोषण ट्रेकर ऐप तथा कुपोषण की जिले वार स्थिति की जानकारी दी। कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों को भारत सरकार के पोषण ट्रेकर ऐप एवं राज्य स्तर से क्रियान्वित संपर्क ऐप के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया।

### शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की लैब का किया उद्घाटन

# समृद्ध भारत की शिक्षित पहचान, कौशल विकासः मंत्री टेटवाल

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने उज्जैन स्थित शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में सीमेंस कम्पनी के सीएसआर फण्ड से निर्मित अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान जॉइंट डारेक्टर सुनील कुमार ललावत, द्वद्वष चेयरमैन राजेश गर्ग, विधायक श्री अनिल जैन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंत्री टेटवाल ने कहा कि मे विद्यार्थी जीवन मैं आईटीआई करके भविष्य निर्माण के बारे में सोचता था, आज सभी के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरी पहचान ITI से है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मंत्री टेटवाल ने कहा कि आईटीआई के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सभी अत्याधुनिक ट्रेड के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जिससे विद्यार्थी स्वरोजगार स्थापित कर, समर्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आईटीआई के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। समृद्ध भारत की शिक्षित पहचान के तहत सभी छात्र-छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए आईटीआई के माध्यम से प्रयोगशालाओं का निर्माण कर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक रोजगार स्थापित हो सके। ह्नमंत्री टेटवाल आईटीआई के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं को पारंपरिक एवं अत्याधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्रों को अत्याधुनिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण मिले इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मंत्री टेटवाल ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य है। कौशल विकास के तहत यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला युवाओं को सशक्त बनाने में कारगर साबित होगी। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण भोपाल में कराया है।

# लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाहीः राज्यमंत्री गौर

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि समय पर काम नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही होगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर सोमवार को गोविंदपुरा क्षेत्र के वार्ड 66 में जनसंपर्क के दौरान जनता की समस्याओं को सुन रही थी। उन्होंने गोविंदपुरा क्षेत्र में जे.के. रोड स्थित गोयल अपार्टमेंट क्षेत्र के रहवासियों द्वारा नाली सफाई, जर्जर सर्विस रोड और रात्रि के समय अंधेरे के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए निर्देश दिए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिक

जिम्मेदारी है। इंद्रपुरी -ए- सेक्टर में जनसंपर्क के दौरान पार्क की स्वच्छता, घास की कटाई एवं सौंदर्यीकरण के लिये आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही नाली में जमा कचरे की शीघ्र सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ लेबर कॉलोनी का निरीक्षण कर रहवासियों से संवाद किया। स्थानीय समस्याओं विशेषकर नाली सफाई, नाली निर्माण और सीवेज लाइन से संबंधित प्रकरणों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। छत्रसाल नगर फेस- 1 के रहवासियों ने बताया कि आसपास की कॉलोनियों में जल भराव हो जाता है।

सड़के जर्जर हो चुकी हैं, पेयजल की भी समस्या है। राज्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बनाने और पानी की टंकी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। रविदास नगर के पार्क में पौधरोपण किया और रहवासियों की मांग पर गणेश उत्सव के पहले शेड निर्माण, पेपर ब्लॉक व फ्लोरिंग कार्य कराए जाने के लिये निर्देश दिए। साथी ही नर्मदा जल के लिए बल्क कनेक्शन दिए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

### टूरिस्ट गाइड रेटिंग सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ गाइड को 2 लाख रूपये की सम्मान राशि

# पर्यटकों के लिए मॉन्यूमेंट गुरु है गाइडः प्रमुख सचिव

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा है कि पर्यटन स्थलों पर गाइड पर्यटकों के मॉन्यूमेंट गुरु होते हैं। पर्यटन स्थल के बारे में जितनी जानकारी गाइड देते हैं उतना ही पर्यटक जान पाते हैं। इसलिए गाइड द्वारा किया पर्यटकों को प्रामाणिक और शोध की गई जानकारी दी जानी आवश्यक है। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में गाइड उन्मुखीकरण और कौशल विकास कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने गाइड्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि टूरिस्ट गाइड रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले गाइड को आगामी वर्ष से पुरस्कार स्वरूप क्रमशः 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये एवं 50 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए गाइड विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें और

मधुर व्यवहार रखें। प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए पर्यटकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी करें। पर्यटन स्थल की जानकारी के साथ प्रदेश की उपलब्धियों और विशेषताओं की जानकारी दें। आसपास के पर्यटन स्थलों से पर्यटकों को अवगत कराएं। इससे मध्यप्रदेश के प्रति पर्यटकों में रुचि बढ़ेगी और वह फिर से पर्यटन के लिए मध्यप्रदेश आयेंगे। सभी गाइड किसी भी पर्यटक के लिए केयर टेकर की भूमिका निभाएं, इससे निश्चित ही पर्यटक सुखद और अविस्मरणीय अनुभव अपने साथ ले जाएंगे। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि आगामी समय में गाइड की संख्या में वृद्धि किए जाने के साथ गाइड को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की जायेगी। साथ ही उनके कौशल को निखारने के लिए तकनीक आधारित वर्कशॉप और ऑनलाइन सेशन लिए जायेंगे। अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड सुश्री बिदिशा मुखर्जी ने कहा कि गाइड्स, पर्यटन विभाग और पर्यटकों के बीच ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं। वे ही प्रदेश और देश के गौरवशाली इतिहास को पर्यटकों से साझा करते हैं। उनकी कुशलता से ही आगंतुकों को हमारी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का ज्ञान होता है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 72 गाइड अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जल्द ही 313 पदों पर गाइड की भर्ती शुरू की जाएगी। सुश्री मुखर्जी ने कहा कि गाइड्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए आगे भी कार्यशालाएं आयोजित जाएगी। गाइड्स को अलगङ्कअलग भाषाओं के ज्ञान के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर श्री भुवन विक्रम सिंह ने कहा कि गाइड्स स्थानीय संस्कृति के परिचायक हैं। वे पर्यटकों के दिग्दर्शक हैं, जो उनकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। भारतीय संस्कृति से विश्व भर के पर्यटकों को अवगत कराते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कार्यरत लाइसेंसधारी राज्य स्तरीय एवं स्थानीय गाइड्स के प्रशिक्षण, कार्यकुशलता में वृद्धि एवं व्यवहारिक दक्षता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा दो दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व संग्रहालय एवं अभिलेखागार भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, IITTM ग्वालियर एवं विषय विशेषज्ञों के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान विषय विशेषज्ञों ने विभिन्न सत्रों में पर्यटन स्थलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तुतिकरण कौशल, नई तकनीक, पर्यटकों के साथ संवाद शैली तथा पर्यटन संबंधी विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है।

### उच्च शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल

# शिक्षा विभाग ने किया 'एपेक्स एडवाइजरी कमेटी' का गठन

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

उच्च शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों पर पुनर्गठित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा अनुसार 'सर्वोच्च परामर्शदायी समिति' (Ape& Advisory Committee) के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। यह समिति उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी, यह पहल 'कर्मयोगी बनें' कार्यक्रम की अनुक्रमिक कड़ी है। समिति के अध्यक्ष उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार और सदस्य सचिव; अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन नामित किए गए हैं। समिति में डॉ. के. राधाकृष्णन चेयरमेन, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, आईआईटी कानपुर, प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे चेयरमेन, ह्वष्ट बेंगलुरु, प्रो. संतिश्री धूलिपुडी पंडित कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, प्रो. आर. बालासुब्रमण्यम सदस्य , कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मिशन कर्मयोगी, भारत सरकार, प्रो. भरत भास्कर, निदेशक, आईआईएम अहमदाबाद, प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, यूजीसी, भारत सरकार, डॉ. विक्रांत सिंह तोमर वैश्विक शिक्षाविद व ग्लोबल कन्वीनर यूनाइटेड कांशसनेस, प्रो. गोविंदन रंगराजन निदेशक, आईआईएससी, बेंगलुरु सदस्य नामित किए गए हैं एवं अपर मुख्य सचिव राजभवन श्री के.सी. गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य नामित हैं। प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विज़न में मध्यप्रदेश के योगदान देने की दिशा में यह 'सर्वोच्च परामर्शदायी समिति' सशक्त आधार प्रदान करेगी। 'सर्वोच्च परामर्शदायी समिति' 'कर्मयोगी बनें' कार्यक्रम से प्राप्त विचारों का विश्लेषण कर ऐसी नीतियाँ सुझायेगी, जिससे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास हो जो विद्यार्थियों को केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ, नवाचारशील और राष्ट्रसेवक नागरिक बनाए, जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में सक्रिय भागीदार बन सकें। समिति के सदस्यगणों का योगदान, मध्यप्रदेश की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने में अत्यंत प्रभावी होगा।

**उच्च शिक्षा मंत्री परमार सर्वोच्च परामर्शदायी समिति के अध्यक्ष होंगे**